



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 08]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 2, 2018/पौष 12, 1939

No. 08]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 2, 2018/PAUSA 12, 1939

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)
जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना
नई दिल्ली, 2 जनवरी, 2018
मामला सं. ओआई-30/2017

विषय :— चीन जनवादी गणराज्य से फ्लोरोइलास्टोमर्स (एफकेएम) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरुआत

सं. 6/25/2017-डीजीएडी :— मै. गुजरात फ्लोरोकैमिकल्स लि. (जिसे आगे "याचिकाकर्ता" या "आवेदक" कहा गया है) ने समय-समय पर यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और समय-समय पर यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें चीन जन. गण. (जिसे आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित फ्लोरोइलास्टोमर्स (एफकेएम) (जिसे आगे संबद्ध वस्तु या विचाराधीन उत्पाद भी कहा गया है) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरुआत करने और पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया गया है।

घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

2. यह आवेदन मै. गुजरात फ्लोरोकैमिकल्स लि. द्वारा घरेलू उद्योग के रूप में दायर किया गया है।

3. आवेदक कंपनी ने दावा किया है कि वह भारत में संबद्ध वस्तु के एकपात्र उत्पादक हैं और बाजार में नये प्रवेशक हैं। इस प्रकार रिकार्ड में उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार, आवेदक कंपनी का उत्पादन घरेलू उत्पादन का प्रमुख हिस्सा बनता है वास्तव में घरेलू उत्पादन का 100 प्रतिशत है। अतः प्राधिकारी निर्धारित करते हैं कि आवेदक कंपनी पाटनरोधी नियमावली के नियम 2 (ख) के अर्थ के भीतर पात्र घरेलू उद्योग हैं और आवेदन पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 (3) के अधीन योग्यता संबंधी मापदंडों को पूरा करता है।

विचाराधीन उत्पाद

4. वर्तमान जांच के विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) फ्लोरोइलास्टोमर्स (एफकेएम) है। फ्लोरोइलास्टोमर्स (एफकेएम) काफी उच्च उत्पादन वाले प्रचालन के लिए डिजाइन किया गया सिंथेटिक रबड़ का एक प्रकार है। उत्कृष्ट समग्र विशेषताओं के चलते फ्लोरोइलास्टोमर्स (एफकेएम) को रबड़ किंग कहा जाता है। इसमें नॉट-फुली-फ्लोरिनेटिड परमाणु संरचन होती है और इसकी मुख्य और पृथक शृंखला में फ्लोरीन अणुओं की मजबूत इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। फ्लोरोइलास्टोमर्स एकल इकाई के बजाय रबड़ों का एक फ्लोरोपालीमर समूह होता है। इससे उनके फ्लोरीन मात्रा क्रमशः 66 प्रतिशत, 68 प्रतिशत और 70 प्रतिशत के अधीन वर्गीकृत किया जा सकता है। एफकेएम को मोटे तौर पर दो समूहों - कापोलिमर और टेरपालीमर में वर्गीकृत किया जाता है।

5. फ्लोरोइलास्टोमर्स (एफकेएम) के विभिन्न अनुप्रयोग होते हैं जैसे हाइड्रोलिक ओ-रिंग सीलों, चेक वाल्व वालों, इलेक्ट्रिकल कनेक्टरों में औद्योगिक प्रयोग, शाफ्ट सीलों, फ्युल इंजेक्टरा ओ-रिंग में आटोमोटिव प्रयोग, ईंधनों, लुब्रिकेंट्स और हाइड्रोलिक प्रणाली, मैनीफोल्ड गैसकेट और ईंधन टैंक के ब्लेडरों में ओ-रिंग सीलों में एअरोस्पेस प्रयोग।

6. इस उत्पाद का कोई समर्पित वर्गीकरण नहीं है। विचाराधीन उत्पाद को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के सीमाशुल्क उप शीर्ष सं. 3904 के अधीन अध्याय 39 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तथापि यह अनुरोध किया जाता है कि सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और उत्पाद के दायरे पर किसी भी तरह से बाध्यकारी नहीं है।

समान वस्तु

7. आवेदक ने दावा किया है कि संबद्ध देश से निर्यातित और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। जैसा आवेदक ने बताया है, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण आदि जैसी विशेषताओं के अनुसार तुलनीय हैं। उपभोक्ता इन दोनों का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं और कर रहे हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं।

8. आवेदक ने यह भी दावा किया है कि ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और इसलिए नियमों के अंतर्गत इन्हें समान वस्तु माना जाना चाहिए। इसलिए वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ, प्राधिकारी ने भारत में आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देश से आयात किए जा रहे विचाराधीन उत्पाद के "समान वस्तु" माना है।

शामिल देश

9. वर्तमान जांच चीन जन. गण. से विचाराधीन उत्पाद के पाटन के संबंध में है।

सामान्य मूल्य

10. याचिकाकर्ताओं ने यह अनुरोध किया है कि वे संबद्ध देश के घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तु की घरेलू विक्री कीमत उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं रहे हैं। याचिकाकर्ताओं ने यह भी दावा किया है कि चीन जन. गण. में उद्योग में काफी विकृतियां प्रचलित हैं। अतः, संबद्ध देश में सामान्य मूल्य का अनुमान भारत में उत्पादन के आधार पर घरेलू उद्योग की सुविधाओं की लागत और परिवर्तन लागत को विक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय और तर्कसंगत लाभ सहित विधिवत रूप से समायोजित करके लगाया गया है।

निर्यात कीमत

11. आवेदकों ने डीजीसीआईएस से प्राप्त आयात आकड़ों के आधार पर चीन जन. गण. के लिए विचाराधीन उत्पाद की निर्यात कीमत निर्धारित की है। संबद्ध देश के लिए समुद्री भाड़े, समुद्री बीमा, पत्तन व्यय, अंतर्देशीय भाड़े, कमीशन और बैंक प्रभारों के लिए कीमत समायोजन किए गए हैं।

पाटन मार्जिन

12. सामान्य मूल्य की तुलना कारखाना-द्वारा निर्यात कीमत के साथ की गई है जिससे संबद्ध देश के संबंध में भारी पाटन मार्जिन का पता चलता है। इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य कारखाना-द्वारा निर्यात कीमत से अधिक है जिससे प्रथम दृष्टया पता चलता है कि संबद्ध देश से निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तु का पाटन किया जा रहा है।

13. भारी पाटन मार्जिन के पर्याप्त साक्ष्य हैं जो पाटनरोधी जांच को उचित ठहराते हैं।

क्षति और कारणात्मक संबंध

14. आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना पर घरेलू उद्योग को हुई क्षति के आकलन के लिए विचार किया गया है। आवेदक ने पाइत आयातों की समग्र रूप से और भारत में उत्पादन और खपत की दृष्टि से बढ़ी हुई मात्रा, कीमत कटौती, कम कीमत पर विक्री, भारी वित्तीय घाटे, नियोजित पूंजी पर ऋणात्मक आय, विभिन्न मापदंडों में नकारात्मक वृद्धि आदि के कारण हुई क्षति के साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। आवेदक ने यह भी दावा किया है कि घरेलू उद्योग के स्थापना में विचाराधीन उत्पाद का पाटन वास्तविक रूप से बाधा डाल रहा है। घरेलू उद्योग के उत्पादन, विक्री, क्षमता उपयोग और बाजार हिस्सा देश में उत्पाद की मांग और इस बात पर विचार करते हुए कि घरेलू उद्योग ने कुछ समय पहले ही वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया है, पर विचार करते हुए काफी कम रहा है।

15. पूर्वोक्त से प्राधिकारी प्रथम दृष्टया यह पाते हैं कि पाटनरोधी जांच की शुरूआत को न्यायोचित ठहराने के लिए संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन, घरेलू उद्योग को हुई क्षति तथा कथित पाटन एवं क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के पर्याप्त साक्ष्य हैं, इसलिए प्राधिकारी एतद्वारा नियमावली के नियम 5 के अनुसार कथित पाटन और घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति की जांच की शुरूआत करते हैं ताकि कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क की उस राशि की सिफारिश की जा सके जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई 'क्षति' को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी।

पाटनरोधी जाँच की शुरूआत

16. पूर्वोक्त पैराग्राफों के मद्देनज़र, निर्दिष्ट प्राधिकारी संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव के संबंध में पाटनरोधी जाँच की शुरूआत करते हैं।

जाँच अवधि (पीओआई)

17. वर्तमान जाँच के प्रयोजनार्थ जाँच अवधि 1 जुलाई, 2016 - 30 जून, 2017 तक की है। तथापि क्षति जाँच अवधि में 2014-15, 2015-16, 2016-17 और जाँच अवधि शामिल होगी।

सूचना प्रस्तुत करना

18. संबद्ध देश में ज्ञात निर्यातकों, भारत में स्थित उनके दूतावास के जरिए उनकी सरकार, भारत में उत्पाद से संबंधित ज्ञात आयातकों व प्रयोक्ताओं को अलग-अलग सूचित किया जा रहा है ताकि वे विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी को नीचे दिए गए पते पर प्रस्तुत कर सकें और अपने विचारों से अवगत करा सकें:

निर्दिष्ट प्राधिकारी
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय
वाणिज्य विभाग,
जीवन तारा बिल्डिंग, चौथा तल,
5 संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001

19. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी जाँच से संगत सूचना संबंधी कोई अनुरोध नीचे दी गई समय सीमा के भीतर निर्धारित ढंग और पद्धति से प्रस्तुत कर सकता है।

समय-सीमा

20. वर्तमान जाँच से संबंधित कोई सूचना और सुनवाई के लिए कोई अनुरोध इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास लिखित में भेजी जानी चाहिए। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी होती है, तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार, रिकार्ड में "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर अपने जाँच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

21. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस जाँच की शुरूआत की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और प्रश्नावली के अपने उत्तर दायर करें तथा घरेलू उद्योग के आवेदन पर और पाटनरोधी उपायों को जारी रखने की आवश्यकता या अन्यथा के संबंध में अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करें।

अगोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

22. यदि प्रश्नावली के उत्तर/अनुरोधों के किसी भाग के संबंध में गोपनीयता का दावा किया जाता है तो ऐसे मामले में निम्नानुसार दो अलग-अलग सैट (क) गोपनीय रूप से अंकित एक सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि); और

(ख). अगोपनीय रूप में अंतिम दूसरा सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि) प्रस्तुत करना होगा। दी गई समस्त सूचना पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए।

23. किसी गोपनीय अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। सभी हितबद्ध पक्षों द्वारा गोपनीय पाठ की दो (2) प्रतियां और अगोपनीय पाठ की पांच (5) प्रतियां प्रस्तुत करना जरूरी होगा।

24. गोपनीय होने का दावा की गई सूचना के लिए में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है और/या ऐसी सूचना का सारांशकरण क्यों संभव नहीं है।

25. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना ,जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है ,पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध /रिक्त छोड़ी गई और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके। तथापि आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों संभव नहीं है।

26. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

27. सार्वक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा। प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

28. नियम 6(7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साध्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

असहयोग

29. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

सुनील कुमार, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)****Initiation Notification**

New Delhi, the 2nd January, 2018

(Case No. OI-30/2017)

Subject:— Initiation of Anti-dumping investigation concerning imports of ‘concerning imports of Fluoroelastomers (FKM) from People’s Republic of China.

F. No. 6/25/2017-DGAD:—M/s Gujarat Fluorochemicals Ltd. (hereinafter referred to as “petitioner” or “the applicant”) have filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act) and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped articles and for Determination of injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Rules) for initiation of anti-dumping investigation and imposition of anti-dumping duty concerning imports of Fluoroelastomers (FKM)(hereinafter also referred to as the subject good or product under consideration), originating in or exported from China PR, (hereinafter also referred to as the subject country).

Domestic Industry & Standing

2. The Application has been filed by M/s Gujarat Fluorochemicals Ltd. as the domestic industry.
3. The applicant company has claimed that they are the sole producer of subject good in India and a new entrant in the market. Thus, as per the evidence available on record, the production of the applicant company constitutes “a major proportion” of the domestic production; in fact 100% share of domestic production. The Authority, therefore, determines that the applicant company constitutes eligible domestic industry within the meaning of Rule 2 (b) of the Anti-Dumping Rules and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5 (3) of the anti-dumping Rules.

Product under consideration

4. The product under consideration (PUC) in the present investigation is Fluoroelastomers (FKM). Fluoroelastomers (FKM) is a class of synthetic rubber designed for very high temperature operation. With excellent over-all properties, Fluoroelastomers (FKM) is called as the "Rubber King. It contains not-fully-fluorinated molecular structure, and its main and side chains contain strong electronegativity of fluorine atoms. "Fluoroelastomers" are a family of fluoropolymer rubbers, not a single entity. It can be classified by

their fluorine content, 66%, 68%, & 70% respectively. FKM are broadly categorized in two sets - Copolymer and Terpolymer.

5. There are various applications of Fluoroelastomers (FKM) such as industrial use in hydraulic O-ring seals, check valve balls, electrical connectors, automotive use in shaft seals, fuel injector O-rings, and aerospace use in O-ring seals in fuels, lubricants & hydraulic system, manifold gaskets and fuel tank bladders.

6. The product does not have dedicated classification. The product under consideration is classified under Chapter 39 under customs subheading no 3904 of the Customs Tariff Act, 1975. It is however submitted that the customs classification is indicative only and in no way it is binding upon the product scope.

Like Article

7. The applicant has claimed that there is no known difference between the subject goods exported from subject countries and that produced by the domestic industry. As submitted by the applicant, the product under consideration produced by the domestic industry and imported from subject country is comparable in terms of essential product characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. Consumers can use and are using the two interchangeably. The two are technically and commercially substitutable.

8. The applicant has further claimed that two are technically and commercially substitutable and, hence, should be treated as 'like article' under the Rules. Therefore, for the purpose of the present investigation, the Authority treats the subject goods produced by the applicant in India as 'Like Article' to the product under consideration being imported from the subject country.

Country involved

9. The present investigation is in respect of dumping of the product under consideration from China PR.

Normal Value

10. The petitioners have submitted that they could not able to provide domestic selling prices of the subject goods in the subject country. The petitioners also claim that there is significant distortions prevailing in the Industry is China PR. Therefore, the Normal Value in the subject country has been estimated on the basis of cost of production in India; taking into account cost of raw material of domestic industry, cost of utilities and conversion cost of domestic industry, duly adjusted on account of selling, general & administration expenses, plus reasonable profit.

Export Price

11. The applicants have determined the export price for the product under consideration for China PR based on the import statistics obtained from DGCI&S imports data. Price adjustments have been made on account of Ocean Freight, Ocean Insurance, Port Expenses, Inland Freight, Commission and Bank Charges for the subject country.

Dumping Margin

12. The normal value and the export price have been compared at ex-factory level, which shows significant dumping margin in respect of the subject country. There is sufficient *prima facie* evidence that the normal values of the subject goods in the subject country are significantly higher than the ex-factory export price, indicating, *prima facie*, that the subject goods are being dumped into the Indian market by the exporters from the subject country.

13. There is sufficient evidence of the significant dumping margins to justify initiation of antidumping investigation.

Injury and Causal Link

14. Information furnished by the applicant has been considered for assessment of injury to the domestic industry. The applicant has furnished evidence regarding the injury having taken place as a result of the alleged dumping in the form of increased volume of dumped imports in absolute terms and in relation to production and consumption, price suppression, price underselling, significant financial losses, negative ROCE, negative growth in various parameters etc. The applicant has also claimed that dumping of the product under consideration is materially retarding the establishment of the domestic industry. The production, sales, capacity utilization and market share of the domestic industry is quite low considering the demand for the product in the Country and considering that the domestic industry commenced commercial production sometime back.

15. From the foregoing, the Authority *prima facie* finds sufficient evidence of dumping of the subject goods originating in or exported from the subject country, injury to the domestic industry and causal link between the alleged dumping and injury exist to justify initiation of an anti-dumping investigation in terms of Para 5 of the Rules, to determine the existence, degree and effect of alleged dumping and to recommend the amount of antidumping duty, which if levied, would be adequate to remove the 'injury' to the domestic industry.

Initiation of anti-dumping investigation

16. The Designated Authority, in view of the foregoing paragraphs, initiates antidumping investigations into the existence, degree and effect of alleged dumping of the subject goods originating in or exported from the subject countries.

Period of Investigation (POI)

17. The period of investigation for the purpose of present investigation is from 1st July, 2016 – 30th June, 2017. The injury investigation period will however, cover the periods 2014-2015; 2015-2016; 2016-2017 and the POI.

Submission of information

18. The known exporters in the subject countries, the Government of the subject countries through their embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the product are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address:

The Designated Authority
Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties
Department of Commerce,
Jeevan Tara Building, 4th Floor
5, Parliament Street
New Delhi -110001

19. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

Time limit

20. Any information relating to the present investigation and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from the date of publication of this Notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Anti-dumping Rules.

21. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses and offer their comments to the domestic industry's application regarding the need to continue or otherwise the Antidumping measures within 40 days from the date of initiation of this investigation.

Submission of Information on Non-Confidential basis

22. In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire's response/submissions, the same must be submitted in two separate sets (a) marked as Confidential (with title, index, number of pages, etc.) and (b) other set marked as Non-Confidential (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either "confidential" or "non-confidential" at the top of each page.

23. Information supplied without any confidential marking shall be treated as non-confidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non-confidential information. Two (2) copies of the confidential version and five (05) copies of the non- confidential version must be submitted by all the interested parties.

24. For information claimed as confidential; the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed and/or why summarization of such information is not possible.

25. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out /summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, parties submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summarization; a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.

26. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

27. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim may not be taken on record by the Authority. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided; shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

Inspection of Public File

28. In terms of rule 6(7) any interested party may inspect the public file containing non-confidential versions of the evidence submitted by other interested parties.

Non-cooperation

29. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

SUNIL KUMAR, Addl. Secy. & Designated Authority